**Corrigendum/Explanation SFG 2024 Level 1 Test 3**

**There are 2 changes in today's paper (Q.28 and Q.38).**
**In Q.28, the correct answer is Option(a), (b), (c), and (d).**
**In Q.38, the correct answer is Option (a), (b), (c), and (d).**

**Q.28 and Q.38-- All the students who have attempted the question will be awarded 2 marks.**

**Also, some extra explanations have been provided to the students who have raised doubts.**

In Q.28) the correct answer is option (a), (b), (c), (d).
A doubt was raised regarding whether statemet translate, rather than option (a), (b), (c), and (d).
Explanation: **The doubt raised is correct.** There are all options are correct, so the answer would be option (a), (b), (c), and (d).

For Future Reference:

**Q.28)** संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करना।
2. भारत सरकार के किसी कर्मचारी से संबंधित सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही।
3. भारत सरकार के अधीन सेवा के दौरान लगी चोटों के संबंध में पेंशन देने का कोई दावा।

उपर्युक्त में से कितने मामलों में यूपीएससी को सरकार से परामर्श लेने की आवश्यकता **नहीं होती है?**

a) केवल एक
b) सिर्फ दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

**Ans) a**

**Exp) विकल्प a सही उत्तर है।**

**संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)** भारत सरकार के तहत विभिन्न सिविल सेवाओं और अन्य पदों पर व्यक्तियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी है। सीधे संविधान द्वारा स्थापित, यूपीएससी को स्वतंत्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 यूपीएससी सदस्यों की

संरचना, नियुक्ति और निष्कासन के साथ-साथ आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्यों के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करते हैं।

**कथन 1 सही है** : निम्नलिखित मामलों को यूपीएससी के कार्यात्मक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित मामलों पर यूपीएससी से परामर्श नहीं किया जाता है:

a) नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय।

b) सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए।

c) आयोगों या न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्चतम राजनयिक प्रकृति के पदों और समूह सी और समूह डी सेवाओं के लिए चयन के संबंध में।

d) किसी पद पर अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्ति के लिए चयन के संबंध में यदि नियुक्त व्यक्ति के एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर बने रहने की संभावना नहीं है।

**कथन 2 गलत है : भारत सरकार के किसी कर्मचारी से जुड़ी सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर** यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए, जिसमें बर्खास्तगी, निष्कासन, रैंक में कमी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति शामिल है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3)(सी) द्वारा अनिवार्य है ।

**कथन 3 गलत है** : अनुच्छेद 320(3)(ई) में कहा गया है कि भारत सरकार के अधीन सेवा करते समय **लगी चोटों के संबंध में पेंशन देने के सभी दावों** और किसी भी प्रश्न पर **संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाएगा ।** ऐसे किसी भी पुरस्कार की राशि.

In Q.38) the correct answer is option (a), (b), (c) and (d).
A doubt was raised regarding whether Statement 1 is missing i.e., Repeat the question in option 1.
Explanation: **The doubt raised is correct.** There are all options are correct, so the answer would be option (a), (b), (c), and (d).

**Q.38)** भारत में 'अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में 'अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य' के विषय का उल्लेख किया गया है।
2. संसद जनहित में किसी राज्य के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है।
3. किसी राज्य के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है।

4. संसद देश में व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

**Ans) c**
**Exp) विकल्प c सही उत्तर है।**
**अनुच्छेद 301 से 307** भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ना और देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक इकाई बनाना है।
**कथन 1 ग़लत है:** 'अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य' का विषय **संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में प्रदान किया गया है।** इसका मतलब यह है कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है, न कि राज्य सरकारों को।
**कथन 2 सही है:** संसद **सार्वजनिक हित में राज्यों के बीच या राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध** लगा सकती है। लेकिन संसद भारत के किसी भी हिस्से में माल की कमी के मामले को छोड़कर एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती या राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती।
**कथन 3 सही है:** किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ विधायिका में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर वरीयता नहीं दे सकती है या राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है।
**कथन 4 सही है:** संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और उस पर प्रतिबंध से **संबंधित प्रावधानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।** संसद उस प्राधिकारी को आवश्यक शक्तियाँ और कर्तव्य भी प्रदान कर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसे किसी प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है.
Source: Laxmikanth